विदेश नीति की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ

नया विज़न
नया जोश

आमुख

इंटरैक्टिव विवरण*

प्रधानमंत्री की यात्राएं

विदेशमंत्री की यात्राएं

अन्य देशों के राजनयिकों की भारत में यात्राएं

कूटनीतिक दस्तावेज़

[*अधिक जानकारी के लिए क्लिक करें]

विदेश नीति की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ

नया विज़न नया जोश

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की सरकार ने हमारी विदेश नीति और कूटनीतिक पहुँच को विशेष महत्व प्रदान किया है। पारंपरिक संबंधों को पुनर्जीवित करना, रणनीतिक संबंधों को फिर से स्थापित करना और विदेशों में रहने वाले भारतीयों तक पहुंचना भारतीय कूटनीति की प्राथमिकता बनी है।

सरकार की कूटनीतिक प्राथमिकता **'पड़ोसी पहले'** को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने मई 2014 में सभी सार्क देशों के नेताओं को शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया था।

इसके बाद प्रधानमंत्री ने अपनी पहली दो विदेश यात्राओं के रूप में, उत्तर में स्थित हमारे दो पड़ोसी और पारम्परिक मित्र देशों, भूटान और नेपाल का दौरा किया। विदेश मंत्री के तौर पर सात में से पांच दक्षिण एशियाई पड़ोसी देशों की मैंने पहले ही यात्रा कर ली है और श्रीलंका के विदेश मंत्री की मेजबानी की है। दुःख और पीड़ा के समय हमने पाकिस्तान के साथ सहयोग किया है।

चाहे दक्षिण एशियाई पड़ोसियों के साथ द्विपक्षीय सहयोग के तहत हाल ही में मालदीव में पानी का घोर संकट उत्पन्न होने पर 'ऑपरेशन नीर' हो, या पड़ोसी देश की एकता और स्थिरता के प्रति भारत की वचनबद्धता के प्रतीक के तौर पर अफगानिस्तान के लोगों को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में सबसे बड़े राष्ट्रीय झंडे का उपहार हो, चाहे 24 वर्षों बाद कोलंबो–जाफना रेल लिंक को दोबारा शुरू करने में सहायता हो, नेपाल, मालदीव व मॉरिशस को 'मेड इन इंडिया' रक्षा निर्यात हो या फिर बहुपक्षीय सहयोग के तहत 2016 तक सार्क का कृत्रिम उपग्रह हो – ये सब कार्य विश्व के अलावा दक्षिण एशिया में एक शांतिपूर्ण, सुरक्षित और समृद्ध राष्ट्र मंडल के अभिन्न अंग के तौर पर भारत के साझे भविष्य के प्रति हमारे सरकार के दृष्टिकोण को प्रतिबिम्बित करते हैं।

प्रधानमंत्री ने नेपाल की संसद में अपने ऐतिहासिक भाषण; और फीजी, जहाँ 'अलग मतदाता सूची' के बिना हाल ही में पहला चुनाव हुआ है, की संसद में अपने भाषण, और भूटान के उभरते संसदीय लोकतंत्र के प्रति अपने महत्वपूर्ण बी4बी भाषण द्वारा यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत सम्पूर्ण विश्व में लोकतन्त्र के लिए आशा की किरण के रूप में तेजी से चमकता रहेगा।

उप–महाद्वीप से बाहर जापान की पहली द्विपक्षीय यात्रा, वर्तमान चीनी राष्ट्रपति की पहली भारत यात्रा, म्यांमार में आसियान–पूर्व एशिया (ASEAN-EAS) शिखर बैठक के बहुपक्षीय समझौते और ऑस्ट्रेलिया की द्विपक्षीय यात्रा के साथ–साथ ब्रिसबेन में जी–20 शिखर बैठक में सहभागिता, वियतनाम के साथ सबसे पहले भारत–प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच (FIPIC) की शुरुआत के साथ तीन उच्च स्तरीय कूटनीतिक अनुबंध, सिंगापुर के साथ मंत्रालयों के स्तर पर कई यात्राओं का आदान–प्रदान और इसके साथ–साथ कोरिया गणराज्य की मेरी हालिया यात्रा ने भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति को क्रियान्वित किया है।

अमेरिका और रूस जैसे सामरिक स्तर के सहयोगियों के

साथ, महत्वपूर्ण ठोस परिणामों के साथ शिखर सम्मेलन स्तर पर अनुबंध पिछले छः महीनों में हमारी राजनयिक सफलता का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

पश्चिम एशिया में हमारे पारंपरिक सहयोगियों के साथ भारत के प्रबल और व्यापक जुड़ाव की झलक प्रधानमंत्री की सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और इज़रायल के प्रधानमंत्री के साथ बैठकों और बहरीन तथा संयुक्त अरब अमीरात के साथ मेरी बैठकों में दिखाई दी। 24 नवम्बर को फिलिस्तीनी लोगों के अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस पर प्रधानमंत्री ने फिलिस्तीन के प्रति भारत के निरंतर समर्थन की फिर से पुष्टि की। और अब जबकि 2014 समाप्ति की ओर अग्रसर है, इराक में 39 भारतीयों के भविष्य के बारे में अनिश्चितता हम सब पर भारी पड़ रही है। हमारे प्रयास निरंतर जारी रहेंगे।

हमारी अभूतपूर्व राजनयिक पहुँच के कारण विदेशों में रहने वाले प्रवासी भारतीय खुद को पहले से अधिक भारत से जुड़ा महसूस कर रहे हैं।

जहाँ प्रधानमंत्री ने न्यूयॉर्क और सिडनी में बड़े जनसमूह को संबोधित किया; वही मैंने प्रादेशिक प्रवासी भारतीय दिवस के लिए यूनाइटेड किंगडम और गिरमिटिया (अनुबंध पर काम करने वाले

मजदूर) लोगों के आगमन के 180वें वर्षगाँठ स्मरणोत्सव के लिए मॉरिशस की यात्रा की।

लीबिया और इराक से ले कर ऑस्ट्रेलिया में सिडनी और यूक्रेन में लुगान्स्क तक जहाँ भी भारतीय नागरिक विपत्ति में फंसे, हमारी सरकार उन्हें हिम्मत बंधाने, बचाव करने और उन्हें सुरक्षित घर वापस लाने के लिए तुरंत मौजूद थी। पिछले छः महीनों में हमने 550 से अधिक भारतीय मछुआरों की श्रीलंकाई जेलों से सफलतापूर्वक सुरक्षित रिहाई करवाई है।

बहुपक्षीय समझौतों ने हमारी विदेश नीति के आर्थिक आधार को आगे लाने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया है।

जुलाई में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में विकासशील देशों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमने नए विकास बैंक की नींव रखी। इस अनूठी नई पहल का पहला अध्यक्ष एक भारतीय होगा।

भारत की अन्तर्राष्ट्रीय व्यस्तताओं के केंद्र में कौशल विकास में सहयोग को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है; बीमारियों के लिए उन्नत चिकित्सा अनुसंधान जैसे कि अमेरिका के

साथ मलेरिया और टीबी जैसी बीमारियों पर अनुसंधान के लिए समझौता, खाद्य सुरक्षा जैसे कि कृषि अनुसंधान पर ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारे कार्य, शिक्षा के क्षेत्र में नई पीढ़ी के

भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थान के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ गठबंधन; क्योटो–वाराणसी, अहमदाबाद–ग्वांगझू और मुंबई–शंघाई जैसे जुड़वां शहरों की व्यवस्था, भारतीय महानगरों में हाई स्पीड रेल लिंक, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ तीन स्मार्ट शहरों के विकास के लिए समझौता – ये सब भारत के तेजी से बढ़ते शहरीकरण को गति प्रदान करेंगे।

भारतीय संस्कृति और मूल्य नई वैश्विक पहचान बना रहे हैं। 11 दिसंबर, 2014 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने अभूतपूर्व 177 'सहप्रायोजक' देशों के साथ 21 जून को 'अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस' घोषित करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया।

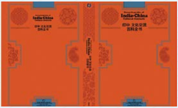

जून में भारत और चीन ने संयुक्त रूप से 'सांस्कृतिक संपर्कों का संग्रह' पेश किया, जो दोनों देशों के बीच सहस्त्राब्दियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों को लिपिबद्ध करने की एक ऐतिहासिक पहल है।

सूचना का समय पर प्रचार–प्रसार करने के लिए भारतीय राजनय ने तकनीक; विशेष रूप से सोशल तथा नए मीडिया प्लेटफॉर्म का प्रयोग किया है; और पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया को सुचारू और तीव्र बनाने की दिशा में कार्य जारी है।

2014 सही मायने में ***राजनय की महत्वपूर्ण उपलब्धि***

का वर्ष रहा है। भारत का सितारा विश्व पटल पर पहले से कही अधिक बुलंदी से चमक रहा है। यह बुकलेट हमारे राजनयिक संवादों के विस्तृत कैनवास को दर्शाती है।

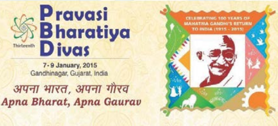

महात्मा गाँधी की भारत वापसी के शताब्दी महोत्सव के दिन प्रवासी भारतीय दिवस, गणतंत्र दिवस के लिए राष्ट्रपति ओबामा की निर्धारित भारत यात्रा, अब तक के सबसे बड़े भारतीय–अफ्रीकी शिखर सम्मेलन की योजनाएं और 'लिंक वेस्ट' नीति के अनुसार नए कदम – ये सब 2015 को और भी अधिक भव्य बनाने को उत्सुक हैं। 2015 में हमारे वैश्विक अनुबंधों के लिए ***'विकास के लिए डिप्लोमेसी'*** अति महत्वपूर्ण मुद्दा है। हम नए जोश और दृढ़ संकल्प के साथ राइजिंग इंडिया विज़न का अनुसरण करेंगे।

सुषमा स्वराज

विदेश मंत्री

नया मन्त्र

‘पड़ोसी पहले’

पड़ोसी

अर्थव्यवस्था

- भारत ने भूटान को 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत 45 अरब भूटानी रूपये और आर्थिक प्रोत्साहन योजना के तहत 5 अरब रूपये की आर्थिक सहायता घोषित की है।
- भूटान को दुग्ध पाउडर, गेहूं, खाद्य तेल, दालों और गैर–बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध से छूट दी गई है।

डिप्लोमेसी

- प्रधानमंत्री की पहली विदेश यात्रा भूटान की थी जिसके थोड़े ही समय बाद 'खास संबंधों' का संकेत देते हुए राष्ट्रपति ने भी भूटान का दौरा किया।

भूटान

शिक्षा

- भूटान के स्कूल में सुधार कार्यक्रम के लिए 348.72 करोड़ रूपये की सहायता घोषित।
- नेहरु–वांग्चुक छात्रवृत्ति को दुगुना करके 2 करोड़ रूपये प्रति वर्ष किया गया।
- भारत द्वारा 33.7 करोड़ की सहायता से भूटान के पहले पॉवर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट की आधार शिला रखी गई।
- भूटान ने नालंदा यूनिवर्सिटी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- भूटान में एक डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने का निर्णय लिया गया जिससे 20 लाख पुस्तकों और पत्रिकाओं तक भूटानी युवाओं की पहुँच होगी।

आधारभूत सुविधाएँ

- 10000 मेगावाट की जल विद्युत् उर्जा के उत्पादन के लक्ष्य को दोहराया।
- 600 मेगावाट की खोलोंग्चु पन–बिजली परियोजना की आधार शिला रखी गई।
- उत्तर पूर्वी–पश्चिमी लेटरल हाइवे को डबल–लेन मार्ग बनाने के लिए भारत द्वारा 46.3 करोड़ रूपये की सहायता।
- भारत की आर्थिक सहायता से बनी भूटान के उच्चतम न्यायालय की ईमारत का उद्घाटन किया गया।

फोटो 1 2
वीडियो
स्नैपशॉट 1 2

डिप्लोमेसी

- जुलाई 2014 में विदेश मंत्री, सुषमा स्वराज ने 23 वर्ष बाद भारत–नेपाल जॉइंट–कमीशन को पुनर्जीवित किया।
- जब प्रधानमंत्री मोदी ने अगस्त 2014 में नेपाल की यात्रा की तो यह 17 वर्षों में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा की गई पहली द्विपक्षीय यात्रा थी। सार्क शिखर सम्मेलन के लिए उन्होंने नवम्बर में दूसरी बार नेपाल की यात्रा की।

रक्षा

- भारत ने ध्रुव मार्क III नामक उन्नत हल्के हेलिकॉप्टर नेपाली सेना को सौंपे।

अर्थव्यवस्था

- भारत ने नेपाल के लिए 1 अरब अमरीकी डॉलर अतिरिक्त ऋण सहायता की घोषणा की।

आधारभूत संरचना

- इलेक्ट्रिक पॉवर ट्रेड के तहत सीमा पार ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन और ग्रिड कनेक्टिविटी के लिए 21 अक्तूबर, 2014 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

पड़ोसी

नेपाल

- 17 वर्षों से लंबित 6720 मेगावाट पंचेश्वर बहुउद्देशीय विकास परियोजना में तेजी लाने के लिए एक समझौता किया गया।
- 900 मेगावाट अरुण– III प्रोजेक्ट के लिए सतलुज जल विद्युत् निगम और इन्वेस्टमेंट बोर्ड ऑफ नेपाल के बीच परियोजना विकास समझौते (पीडीए) पर हस्ताक्षर किए गए; 900 मेगावाट अपर करनाली परियोजना के लिए एक और पीडीए पर करार किया गया।
- काठमांडू में 200 बिस्तर वाले इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर इकाई का उद्घाटन किया गया।
- एक मोटर वाहन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और दिल्ली–काठमांडू पशुपतिनाथ एक्सप्रेस बस सर्विस का भी शुभारंभ किया गया।
- 550 करोड़ की लागत से बनने वाली राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
- सिस्टर–सिटी व्यवस्था के लिए निम्नलिखित जगहों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किये गए

  –अयोध्या – जनकपुर
  –बोध गया – लुंबिनी
  –वाराणसी – काठमांडू

फोटो 1 2 3
वीडियो
स्नैपशॉट 1 2 3 4 5

पड़ोसी

डिप्लोमेसी

- जून 2014 में विदेशमंत्री ने अपनी पहली यात्रा के रूप में बांग्लादेश का दौरा किया।

- भारत–बांग्लादेश ने नई दिल्ली में भारत–बांग्लादेश जॉइंट कमीशन की तीसरी बैठक की।
- ढाका–कोलकाता मैत्री एक्सप्रेस की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई गई।
- 13 वर्ष से कम और 65 वर्ष से अधिक आयु के बांग्लादेशी नागरिकों को 5 वर्ष का एकाधिक प्रवेश वीज़ा देने का प्रस्ताव दिया गया।

बांग्लादेश

आधारभूत संरचना

- भारत ने त्रिपुरा के पलाताना प्रोजेक्ट से बांग्लादेश को 100 मेगावाट अतिरिक्त बिजली बेचने का निर्णय किया।
- गुवाहाटी–ढाका बस सेवा हेतु मार्ग सर्वेक्षण प्रारंभ।
- बांग्लादेश ने स्थलरुद्ध पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में खाद्यान्नों के परिवहन के लिए भारत को अपने क्षेत्र और बुनियादी सुविधाओं के प्रयोग की अनुमति दी।
- मेघालय में चार और सीमा हाट खोलने पर निर्णय।
- बांग्लादेश ने भारतीय कंपनियों को उद्योग लगाने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र का प्रस्ताव दिया।

शिक्षा

- भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग कार्यक्रम (आईटीईसी) के तहत प्रशिक्षण स्लॉट्स 185 से बढ़ा कर 215 किए गए।
- भारत, शान्ति निकेतन में बांग्लादेश भवन की स्थापना के लिए सहायता प्रदान करेगा।
- बांग्लादेश ने नालंदा यूनिवर्सिटी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

डिप्लोमेसी

- विभिन्न बहुपक्षीय बैठकों के अलावा प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति राजपक्षे के बीच लगातार उच्च स्तरीय बैठकें।

फोटो
वीडियो
स्नैपशॉट

श्रीलंका

- श्रीलंका में मौत की सजा का सामना कर रहे पांच भारतीय मछुआरों को बिना शर्त रिहा किया गया। सरकार द्वारा उच्चतम स्तर पर अथक प्रयासों के पश्चात् श्रीलंका के राष्ट्रपति ने पाँचों मछुआरों की सजा में पूर्ण छूट दी।
- नई सरकार द्वारा काम काज शुरू किए जाने के बाद अब तक 550 भारतीय मछुआरे रिहा किए गए हैं।

आधारभूत संरचना

- भारत द्वारा 800 मिलियन डॉलर की रिआयती ऋण सहायता के साथ 38 किलोमीटर लंबी पल्लई–जाफना रेलवे लाइन का श्रीलंका में पुनर्निर्माण किया गया।
- भारत द्वारा उत्तरी और पूर्वी प्रान्तों में विकास परियोजनाओं, विशेष रूप से आवासीय परियोजना की समीक्षा।

संस्कृति

- भारत के राष्ट्रपति द्वारा श्रीलंका के बौद्ध भिक्षु अनागारिका धर्मपाला पर विशेष संस्मारक डाक टिकट जारी की गई।

डिप्लोमेसी

- मालदीव के जल शोधक संयंत्र के आग से नष्ट होने पर वहां के विदेश मंत्री द्वारा हमारे विदेश मंत्री से सहायता प्रदान करने के अनुरोध के 24 घंटे के भीतर भारत ने माले की साहयता के लिए ऑपरेशन नीर को अंजाम दिया। भारतीय वायुसेना के मालवाहक विमानों और नौसेना के जहाजों ने पीने का पानी पहुंचाया।

पड़ोसी

मालदीव

फोटो 1 2

वीडियो

स्नैपशॉट 1 2

पड़ोसी

डिप्लोमेसी

- राष्ट्रीय एकता के प्रतीक के तौर पर अफगानिस्तान को उपहार में दिए गए 207 फीट लम्बे झंडे के स्तंभ के उदघाटन समारोह में भाग लेने के लिए विदेश मंत्री ने काबुल का दौरा किया। एक

अफगानिस्तान

राष्ट्रीय स्मारक के तौर पर इसके चारों ओर की साईट विकसित करने के लिए भारत ने दस लाख अमरीकी डॉलर की मदद का वादा किया।

- विदेश मंत्री सुषमा स्वराज द्वारा नए भारतीय दूतावास और कार्यालय परिसर का उदघाटन किया गया।
- पीएम मोदी और राष्ट्रपति अशरफ गनी के बीच सार्क शिखर सम्मेलन से हट कर विस्तृत वार्ता हुई। 2015 के प्रारंभ में राष्ट्रपति गनी भारत का दौरा करेंगे।

पड़ोसी

फोटो

वीडियो

स्नैपशॉट

पाकिस्तान

- दुःख और पीड़ा के समय भारत ने पाकिस्तान के साथ सहयोग की पेशकश की।
- पेशावर में बर्बर आंतकवादी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ से फोन पर बात की। उन्होंने कड़े शब्दों में इस हमले की निंदा की और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से कहा कि साझा दुःख और शोक का यह क्षण दोनों देशों और उन सभी देशों के लिए एक संकेत है जो मानवता में विश्वास रखते हुए एकजुट हो कर निर्णायक और पूर्ण रूप से आंतकवाद का खात्मा करना चाहते हैं।

द्विपक्षीय संबंधों को

ताजा प्रोत्साहन

डिप्लोमेसी

- द्विपक्षीय संबंधों को प्रदर्शित करने के लिए उच्चतम स्तर पर नियमित बैठकें।
- राष्ट्रपति शी जिनपिंग के विशेष दूत के रूप में विदेश मंत्री वांग यी भारत का दौरा करने वाले पहले विदेश मंत्री थे।
- राष्ट्रपति शी जिनपिंग 2005 के बाद भारत की यात्रा करने वाले पहले चीनी राष्ट्रपति थे।
- पीएम मोदी ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग से ब्रिक्स शिखर बैठक और जी–20 शिखर सम्मेलन में भी मुलाकात की, और ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन में चीनी प्रधानमंत्री ली केक्यांग से भी मिले।

अर्थव्यवस्था

- चीन के साथ विशाल व्यापार असंतुलन पर बात हुई।
- गुजरात और महाराष्ट्र में दो औद्योगिक पार्क स्थापित करने के लिए चीन को अनुमति देने के साथ 6.8 बिलियन डॉलर के एक सौदे पर करार हुआ।
- चीन के साथ एक पंचवर्षीय व्यापार एवं अर्थव्यवस्था विकास योजना पर हस्ताक्षर किए गए।
- अगले पांच वर्षों में चीन भारत में 20 बिलियन डॉलर के निवेश के लिए सहमत
- हाई–स्पीड ट्रेनों में सहयोग की संभावना का अध्ययन करने के साथ–साथ रेलवे क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा।
- सीमा शुल्क में परस्पर प्रशासनिक सहायता और सहयोग

अंतरिक्ष

- अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए।

P5 देश

चीन

संस्कृति

- कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने वाले भारत के वृद्ध तीर्थयात्रियों के लाभ के लिए अतिरिक्त मोटर योग्य मार्ग को खोलने के लिए समझौता
- सांस्कृतिक संपर्कों को बढ़ावा देने के लिए दोनों देश भारत–चीन सांस्कृतिक आदान–प्रदान पहल शुरू करने के लिए सहमत।
- 2015 को 'भारत यात्रा वर्ष' और 2016 को 'चीन यात्रा वर्ष' के रूप में मनाया जाएगा।
- दोनों सरकारों के बीच ऑडियो विजुअल सह–निर्माण के लिए समझौता।
- भारत–चीन सांस्कृतिक संपर्कों के संग्रह का लोकार्पण किया गया।

डिप्लोमेसी

- 15वां वार्षिक भारत–रूस शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने संयुक्त बयान द्वारा द्विपक्षीय संबंधों के लिए रोडमैप जारी किया। 'द्रुज्बा–दोस्ती' अगले दशक में भारत रूस साझेदारी को और सुदृढ़ करने का एक दृष्टिकोण है।

रक्षा

- भारतीय सशस्त्र बलों को रूसी सैन्य शैक्षिक संस्थानों में प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- रूस ने प्रति वर्ष भारत में 400 एमआई–17 मीडियम लिफ्ट और कामोव केए–226 हल्के यूटिलिटी हेलिकॉप्टरों की असेम्बली के लिए प्रस्ताव पेश किया है जो कि 'मेक इन इंडिया' अभियान के लिए एक प्रमुख प्रोत्साहन है।

रूस

अर्थव्यवस्था

- वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार तथा निर्बाध निवेश के लिए भारत तथा रूस, बेलारूस और कजाखस्तान के सीमा शुल्क संघ के बीच वार्ता शुरू करने का निर्णय लिया गया।
- अगले दो दशकों में रूस भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 12 और परमाणु रिएक्टर बनाने के लिए सहमत।
- भारत में डायमंड एक्सचेंज और रूस से भारत को कच्चे हीरे के प्रत्यक्ष निर्यात द्वारा द्विपक्षीय हीरा व्यापार को बढ़ावा।

आधारभूत संरचना

- रूसी कंपनी सिस्टेमा की सहायता से भारत में एक स्मार्ट सिटी स्थापित करने की योजना।

विज्ञान और तकनीक

- दूरसंचार उपग्रहों के समूह नेक्स्ट स्टार को कम लागत के प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जाएगा।
- रूस में पोटेशियम और मैग्निशियम भंडारों के विकास के लिए भारतीय कंपनी राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एनएमडीसी) और रूसी कंपनी एक्रोन के बीच संयुक्त सहयोग के एक समझौते पर हस्ताक्षर।

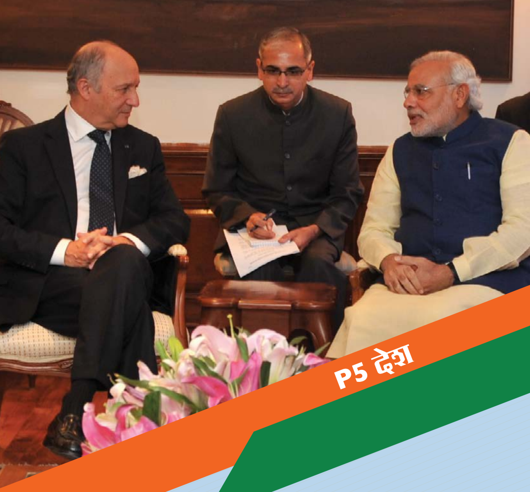

P5 देश

डिप्लोमेसी

- विदेश मंत्री लॉरेंट फैबियस ने जून में भारत की यात्रा की।
- जी–20 शिखर सम्मेलन के दौरान भी प्रधानमंत्री मोदी ने भी फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रेंकोइस होलैंड से भेंट की।

फ्रांस

फोटो

वीडियो

स्नैपशॉट
1 2

P5 देश

फोटो
वीडियो
स्नैपशॉट 1 2 3

यूनाइटेड किंगडम

डिप्लोमेसी

- जुलाई में विदेश मंत्री ने नई दिल्ली में यूके के पूर्व विदेश सचिव विलियम हेग की मेजबानी की। संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान उन्होंने नए विदेश सचिव फिलिप हेमंड से भेंट की।
- विदेश मंत्री ने लंदन का दौरा भी किया और यूके के उपप्रधानमंत्री निक क्लेग से मुलाकात की।
- ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरून ने जी–20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की; और बताया कि भारत के साथ संबंध यूके की विदेश नीति की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
- अहमदाबाद स्थित ब्रिटिश ट्रेड ऑफिस को डिप्टी हाई कमीशन के रूप में अपग्रेड किया गया।
- लंदन के पार्लियामेंट स्क्वेयर में महात्मा गाँधी का बुत लगाया जाएगा।

डिप्लोमेसी

- 26 से 30 सितंबर, 2014 तक प्रधानमंत्री ने अमेरिका की यात्रा की।
- पीएम मोदी और राष्ट्रपति ओबामा ने एक अमेरिका–भारत विज़न स्टेटमेंट जारी किया जिसका शीर्षक है – 'चलें साथ–साथ' – फॉरवर्ड टुगेदर वी गो'।
- आंतकवाद से लड़ने का प्रयास, सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार (डब्ल्यूएमडी), परमाणु आंतकवाद, सीमा पार अपराध और आंतक फैलाने के लिए इंटरनेट के दुरूपयोग को ले कर दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई।

रक्षा

- भारत–अमेरिका रक्षा सहयोग के फ्रेमवर्क एग्रीमेंट का आगामी 10 वर्षों के लिए नवीकरण।
- भारत के योजनाबद्ध राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के लिए अमेरिका नॉलेज–पार्टनर के रूप में सहयोग करेगा।

अर्थव्यवस्था

- भारत और अमेरिका ने द्विपक्षीय व्यापार को वर्तमान में 100 बिलियन डॉलर से पांच गुणा बढ़ा कर 500 बिलियन डॉलर करने का निर्णय लिया।
- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को सुविधाजनक बनाने और बुनियादी ढाँचे के वित्तपोषण को ध्यान में रखते हुए भारत–अमेरिका निवेश पहल शुरू की गई।

शिक्षा

- शैक्षणिक नेटवर्क की वैश्विक पहल के तहत शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों के 1000 अध्यापक प्रतिवर्ष भारतीय केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अध्यापन के लिए आएँगे।
- भारत के नए एम्स–राष्ट्रीय कैंसर संस्थान की स्थापना के लिए अमेरिका सहयोग करेगा।

ऊर्जा

- भारत में स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में वाणिज्यिक विकास गतिविधियों के दौरान प्रयुक्त होने वाली अमेरिकन तकनीक, उत्पाद और सेवाओं के वित्तपोषण के लिए, यूएस एक्सिम बैंक 1 बिलियन डॉलर का ऋण उपलब्ध कराएगा।

P5 देश

संयुक्त राज्य अमेरिका

आधारभूत संरचना

- अमेरिकी कंपनियों के सहयोग से इलाहाबाद, अजमेर और विशाखापत्तनम के शहरों को 'स्मार्ट सिटी' के रूप में विकसित किया जाएगा।

विज्ञान और तकनीक

- फर्मिलैब के साथ प्रोटोन एक्सीलेटर प्रोजेक्ट और थर्टी मीटर टेलिस्कोप संघ में भारत की सदस्यता सम्पन्न।
- भारत में अमेरिकी मूल के परमाणु रिएक्टरों को लगाने की योजना में तेजी लाने के लिए एक इंटर–एजेंसी कार्य समूह बनाया गया।

अंतरिक्ष

- मंगल अन्वेषण पर सहयोग करने के लिए एक संयुक्त कार्य दल गठित किया जाना है।

फोटो
वीडियो
स्नैपशॉट
1 2 3 4

लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई देश बाधाएं होंगी पार,

डिप्लोमेसी

- ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए ब्राजील की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कई लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई देशों के नेताओं से मुलाकात की और ब्राज़ील के राष्ट्रपति रोसेफ से द्विपक्षीय चर्चा भी की।
- ब्रासिलिया में लैटिन अमेरिकी देशों के नेताओं से भेंट होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे कहा; "दूरी

मिटेंगी दूरियां

अवसरों के लिए बाधक नहीं है"।

- पहली बार नई दिल्ली में विदेश मंत्री स्तर पर भारत–मैक्सिको संयुक्त आयोग बैठक (जेसीएम) हुई।
- लैटिन अमेरिकी देशों, जिनमें निकारागुआ, ग्वाटेमाला, बोलीविया, कोलंबिया और इक्वाडोर भी शामिल थे, के साथ विदेश कार्यालय स्तर पर विचार–विमर्श हुआ।

व्यापार और निवेश

- भारत और ब्राज़ील IRS उपग्रहों से डेटा प्राप्त करने और प्रोसेस करने के लिए एक ब्राजीलियाई अर्थ स्टेशन के विस्तार में सहयोग के लिए सहमत।
- भारत–एलएसी इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव के जरिए भारत और एलएसी देशों के बीच दो वर्षों में व्यापार को दुगना करके 42 बिलियन डॉलर (2.62 लाख करोड़ रुपये) करने का प्रयास किया जा रहा है।

फोटो
वीडियो
स्नैपशॉट

'लुक ईस्ट' से

‘एक्ट ईस्ट’ तक

एक्ट ईस्ट

डिप्लोमेसी

- साउथ एशिया से बाहर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पहली द्विपक्षीय विदेश यात्रा जापान की थी।
- प्रधानमंत्री मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने वास्तविक दुनिया और सोशल मीडिया को व्यक्तिगत घनिष्ठता द्वारा प्रभावित किया।
- 'विशेष सामरिक और वैश्विक भागेदारी' के लिए भारत–जापान संबंधों को बढ़ावा।

रक्षा

- रक्षा के क्षेत्र में सहयोग और आदान–प्रदान के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

जापान

आधारभूत संरचना

- क्योटो और वाराणसी के बीच सिस्टर सिटी संबंध स्थापित करने के एक समझौते पर दस्तखत किए गए।

अर्थव्यवस्था

- जापान द्वारा आगामी पांच वर्षों में निजी और सार्वजनिक निवेश 3.5 ट्रिलियन येन (2,10,000 करोड़ रूपये) तक पहुँचाने की घोषणा।
- जापान ने मुम्बई और अहमदाबाद के बीच 60,000 करोड़ रूपये की बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए वित्तीय, तकनीकी और परिचालन सहयोग की इच्छा जताई।
- जापान ने एचएएल सहित छः भारतीय कंपनियों से बैन हटाया।

एक्ट ईस्ट

डिप्लोमेसी

- विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने अगस्त में म्यांमार की यात्रा की।
- प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति थिन सेन ने अपनी बैठक के दौरान निम्न पर ध्यान केन्द्रित किया:
  - बेहतर कनेक्टिविटी
  - सांस्कृतिक संपर्कों को बढ़ावा
  - मजबूत वाणिज्यिक संबंध
- प्रधानमंत्री ने आंग सान सू की से भी भेंट की और उन्हें "लोकतन्त्र का प्रतीक" बताया।

आधारभूत संरचना

- प्रमुख आधारभूत संरचना परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा

म्यांमार

की गई:

– 3200 किलोमीटर लम्बा भारत–म्यांमार–थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग।

– क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ाने के उद्देश्य से कलादान मल्टी–मॉडल ट्रांसपोर्ट परियोजना. यह परियोजना समुद्र द्वारा कोलकाता को म्यांमार में सितवे से जोड़ेगी; म्यांमार में कलादान से होकर नदी नाव मार्ग से सितवे से लाशियो और लाशियो से सड़क मार्ग द्वारा मिजोरम को जोड़ेगी।

- म्यांमार में विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) में भारतीय निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की गई।
- ऑयल इंडिया ने म्यांमार में दो अपतटीय तेल और गैस ब्लॉक का पता लगाने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए।

संस्कृति

- दोनो देशों के बौद्ध धर्म से जुड़े होने के कारण प्रधानमंत्री ने इसे दोनों देशों के "परस्पर भाईचारे का संबंध" बताया।

डिप्लोमेसी

- दोनों देशों के बीच उच्च–स्तरीय बैठकें आयोजित की गईं – सिंगापुर के विदेश मंत्री और सेवामुक्त वरिष्ठ मंत्री ने भारत का दौरा किया। अगस्त में विदेश मंत्री ने सिंगापुर की यात्रा की।
- प्रधानमंत्री मोदी ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सीन लुंग से ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन से परे मुलाकात की।
- भारत और सिंगापुर के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने पर 'ईयर ऑफ इंडिया' का उदघाटन किया गया।

अर्थव्यवस्था

- निवेश और व्यापार को बड़े पैमाने पर बढ़ाने के लिए एक समझौते पर दस्तखत भी किए गए।

आधारभूत संरचना

- दिल्ली–मुम्बई और चेन्नई–बेंगलुरु औद्योगिक गलियारों तथा उत्तर–पूर्व भारत की कौशल परियोजनाओं में कनेक्टिविटी और आधारभूत संरचना से जुड़ी परियोजनाओं की गति तेज करने के लिए भारत में सिंगापुर की कंपनियों को आमंत्रित किया गया।
- भारत में स्मार्ट सिटी पहल के तहत जल संरक्षण और रीसाइक्लिंग परियोजनाओं में सिंगापुर की भागीदारी अपेक्षित।

एक्ट ईस्ट

सिंगापुर

एक्ट ईस्ट

डिप्लोमेसी

- पहली बार एक ही वर्ष में ऑस्ट्रेलियाई और भारतीय प्रधानमंत्रियों द्वारा पारस्परिक यात्रा।
- प्रधानमंत्री मोदी पिछले 28 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री। उन्होंने ब्रिसबेन, मेलबोर्न, सिडनी और कैनबरा की यात्रा की।
- प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलियाई संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री।
- कला और संस्कृति, पर्यटन, मादक पदार्थों की तस्करी से निबटने, सजायाफ्ता व्यक्तियों के स्थानान्तरण, सामाजिक सुरक्षा के लाभ और कवरेज जैसे विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े 5 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए गए।

ऑस्ट्रेलिया

रक्षा

- अनुसंधान, विकास और उद्योग के लिए रक्षा सहयोग विस्तारित।
- सुरक्षा सहयोग के लिए एक ढांचा तैयार किया गया, जिसमे आंतकवाद से मुकाबले तथा मेरीटाइम एक्सचेंज के लिए अधिक सहयोग पर बल दिया गया है, पर हस्ताक्षर किए गए।

ऊर्जा

- प्रधानमंत्री एबॉट की भारत यात्रा के दौरान परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग से जुड़े एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
- चूंकि ऊर्जा आर्थिक संबंधों का प्रमुख पहलू है, अतः दोनो प्रधानमंत्री प्रमुख खनन निवेश परियोजनाओं की मंजूरी की प्रक्रिया में तेजी लाने पर सहमत हुए।

संस्कृति

- ऑस्ट्रेलिया ने भारत को दो प्राचीन उत्कृष्ट प्रतिमाएं वापिस सौंपी, जिन्हें कथित रूप से तमिलनाडु के मन्दिरों से चुराया गया था – इन में से एक नटराज शिव की प्रतिमा और दूसरी अर्धनारीश्वर की प्रतिमा थी।

फोटो
वीडियो 1 2
स्नैपशॉट 1 2 3

डिप्लोमेसी

- प्रधानमंत्री मोदी पिछले 33 वर्षों में फीजी की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री, जिन्होंने नवम्बर 2014 को फीजी की यात्रा की।
- भारत द्वारा सफलतापूर्वक भारत–प्रशांत द्वीपसमूह सहयोग मंच (एफ आई पी आई सी) – प्रशांत क्षेत्र के द्वीपसमूह देशों के साथ उच्च स्तरीय संपर्क तंत्र – की शुरुआत।
- भारत फीजी के नए संसदीय पुस्तकालय के भवन निर्माण में सहयोग करेगा।

एक्ट ईस्ट

- भारत में फीजी के युवा राजनयिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

रक्षा

- रक्षा प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए फीजी को सहायता दी जानी है।

अर्थव्यवस्था

- सह–उत्पादक बिजली संयंत्र के लिए फीजी को 70 मिलियन डॉलर ऋण प्रदान किया गया।
- लघु और ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भारत द्वारा 5 मिलियन डॉलर की राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

शिक्षा

- फीजी के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति और प्रशिक्षण स्लॉट को दुगना किया गया।

फीजी

फोटो

वीडियो
1 2

स्नैपशॉट
1 2

डिप्लोमेसी

- विदेश मंत्री ने अगस्त में हनोई का दौरा किया।
- भारत के राष्ट्रपति ने सितम्बर में वियतनाम की यात्रा की।
- वियतनाम के प्रधानमंत्री गुयेन टैन डंग ने अक्तूबर 2014 में भारत की यात्रा की।

अर्थव्यवस्था

- भारत से रक्षा पोत हासिल करने के लिए वियतनाम को 100 मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान किया गया।
- 2020 तक भारत और वियतनाम के बीच द्विपक्षीय व्यापार के बढ़ कर 15 बिलियन डॉलर होने का अनुमान।
- ओएनजीसी विदेश लिमिटेड और पेट्रो वियतनाम के बीच आशय–पत्र पर हस्ताक्षर किए गए।
- जेट एयरवेज़ (भारत) और विएतनाम एयरलाइंस कम्पनी लिमिटेड के बीच सीधी उड़ानों के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए।

शिक्षा

- वियतनाम ने नालंदा यूनिवर्सिटी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- न्हा ट्रांग के दूरसंचार विश्विद्यालय में वियतनाम–भारत इंग्लिश और आई टी प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए।

संस्कृति

- 2015–17 अवधि के लिए एक सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रम शुरू किया गया।
- माई सन के विश्व विरासत स्थल पर मन्दिरों के समूह के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए वियतनाम को भारत के समर्थन के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए।

एक्ट ईस्ट

वियतनाम

फोटो 1 2 3

वीडियो

स्नैपशॉट 1 2 3 4

एक्ट ईस्ट

डिप्लोमेसी

- 28–30 दिसंबर को विदेश मंत्री सियोल में अपने समकक्ष कोरिया गणराज्य (आरओके) के विदेश मंत्री श्री युन ब्युंगसे के साथ भारत–कोरिया गणराज्य संयुक्त आयोग की सह–अध्यक्षता करेंगी।
- प्रधानमंत्री मोदी ने ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति पार्क ग्यून हाई से भेंट की।

कोरिया गणराज्य

अर्थव्यवस्था

- प्रधानमंत्री और विदेशमंत्री द्वारा कोरियाई उद्योग, विशेष रूप से 'सहयोगी के तौर पर 'मेक इन इंडिया' पहल से जुड़ने की भारत की तत्परता से कोरियाई नेताओं को अवगत कराया गया।

फोटो वीडियो स्नैपशॉट

मजबूत संबंध

पुराने मित्रों के साथ

पश्चिम एशिया

ओमान

डिप्लोमेसी

- ओमान के विदेश मामलों के मंत्री युसूफ बिन अलवी बिन अब्दुल्ला जून में भारत की यात्रा करने और विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज से भेंट करने वाले पहले विदेश मंत्री थे।
- अंतर्राष्ट्रीय अपराधों और विभिन्न प्रकार के आंतकवाद को मिटाने हेतु ठोस संबंधों के मार्ग को प्रशस्त करने वाली एक संधि पर दस्तखत किए गए।

पश्चिम एशिया

बहरीन

डिप्लोमेसी

- विदेश मंत्री द्वारा खाड़ी क्षेत्र में की गई पहली यात्रा बहरीन की थी, जो इस क्षेत्र में ऊर्जा सुरक्षा, प्रवासी भारतीयों और व्यापार संबंधों के रूप में भारत के उच्च हितों को रेखांकित करती है।

फोटो

वीडियो

स्नैपशॉट
1 2

डिप्लोमेसी

- विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने नवम्बर 2014 में संयुक्त अरब अमीरात का दौरा किया।

अर्थव्यवस्था

- विदेश मंत्री ने आबू धाबी में उद्योग प्रमुखों को भारत की विकास यात्रा और 'मेक इन इंडिया' अभियान में भागीदार बनने के लिए कहा।
- विदेश मंत्री ने बड़ी संख्या में दुबई में बसने वाले विशाल भारतीय समुदाय से भी भेंट की।

पश्चिम एशिया

संयुक्त अरब अमीरात

फोटो

वीडियो

स्नैपशॉट
1 2

पश्चिम एशिया

सऊदी अरब

डिप्लोमेसी

- जी–20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री श्री मोदी ने क्राउन प्रिंस सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ से भेंट की।
- क्राउन प्रिंस ने भारत को "अत्यधिक मित्रवत देश" बताया जिसके साथ सऊदी अरब प्रत्येक क्षेत्र में सहयोग के लिए तैयार है।

फोटो वीडियो स्नैपशॉट

पश्चिम एशिया

फिलिस्तीन

- विदेश मंत्री ने नई दिल्ली में फिलिस्तीन राज्य के राष्ट्रपति के विशेष दूत डा० नबील शाथ से मुलाकात की।
- अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस के अवसर पर फिलिस्तीनी लोगों को दिए गए एक संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि इज़रायल के साथ अच्छे संबंधों को बरकरार रखते हुए, फिलिस्तीनी हितों के लिए पारंपरिक रूप से मजबूत समर्थन देने की भारत की नीति में कोई बदलाव नहीं होगा।
- 26 सितम्बर 2014 को फिलिस्तीन में हुई गुटनिरपेक्ष देशों की मंत्रीस्तरीय बैठक में भाग लेते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि गुट निरपेक्ष आन्दोलन के एक संस्थापक सदस्य के रूप में भारत ने हमेशा फिलिस्तीनी लोगों के हितों का समर्थन किया है और यह हमारी विदेश नीति की मुख्य विशेषता है। उन्होंने यह भी कहा कि फिलिस्तीन के सवाल पर हमारा रुख महात्मा गांधी के नेतृत्व में हमारे अपने स्वतंत्रता संग्राम से प्रेरित था।

पश्चिम एशिया

इज़रायल

डिप्लोमेसी

- संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान प्रधानमंत्री ने इज़रायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू से मुलाकात की और विभिन्न द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की।
- इसके बैठक के बाद विदेश मंत्री और उनकी इज़रायली समकक्ष के बीच न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान बैठक हुई।

फोटो वीडियो स्नैपशॉट

स्वच्छ ऊर्जा के लिए निवेश

डिप्लोमेसी

- पीएम मोदी ने जी–20 शिखर सम्मेलन से परे जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल से भेंट की।
- जर्मन विदेश मंत्री डा० फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर ने सितम्बर में भारत का दौरा किया और विदेश मंत्री से विस्तार से चर्चा की।
- राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अक्तूबर 2014 में नॉर्वे और फिनलैंड की यात्रा की।
- राज्यमंत्री जनरल वी० के० सिंह ने स्लोवेनिया की यात्रा की और 9वें ब्लेड सामरिक मंच में भाग लिया – यह सामरिक वार्ता को बढ़ावा देने और सामयिक वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हेतु एक मंच बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय उच्च–स्तरीय सम्मेलन था।

अर्थव्यवस्था

- हेनोवर मेसे 2015 में भारत के सहयोगी राष्ट्र के रूप में भाग लेने के चांसलर मर्केल के निमंत्रण को पीएम मोदी ने स्वीकार कर लिया।
- जर्मनी द्वारा व्यवसायिक कौशल में भारतीय युवाओं के प्रशिक्षण के लिए "कुशल भारत, कुशल जर्मनी – दोहरी प्रणाली: राज्य और व्यापार" की शुरुआत की गई।

यूरोप

वास्तविक और आभासी नेटवर्क से कनेक्टेड

डिप्लोमेसी

- विदेश मंत्री ने 180वें अप्रवासी दिवस के स्मरणोत्सव में भाग लिया, जो मॉरिशस में पहले भारतीय अनुबंधित श्रमिक (गिरमिटिया) के आगमन की वर्षगाँठ के तौर पर मनाया जाता है।

अर्थव्यवस्था

- डीटीएए में संशोधनों पर चर्चा।

अफ्रीका

मॉरिशस

फोटो

वीडियो

स्नैपशॉट

1 2

अफ्रीका

फोटो

वीडियो

स्नैपशॉट

दक्षिण अफ्रीका

डिप्लोमेसी

- दक्षिण अफ्रीका की मानव प्रवासन मंत्री लिंडवे नोंकेबा सिसुलु ने विदेश मंत्री से मुलाकात की और देश की स्वतन्त्रता में भारत द्वारा निभाई गई भूमिका के बारे में चर्चा की।
- संयुक्त राष्ट्र और ब्रिक्स जैसे बहुपक्षीय मंचों पर घनिष्ठ सहयोग दोहराया गया।

संस्कृति

- 2015 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी की भारत वापसी के 100 वर्ष पूरे होने पर समारोह आयोजित किया जाएगा। दक्षिण अफ्रीकी विदेश मंत्री माइते न्कोना मशाबाने प्रवासी भारतीय दिवस 2015 की विशिष्ट अतिथि होंगी।

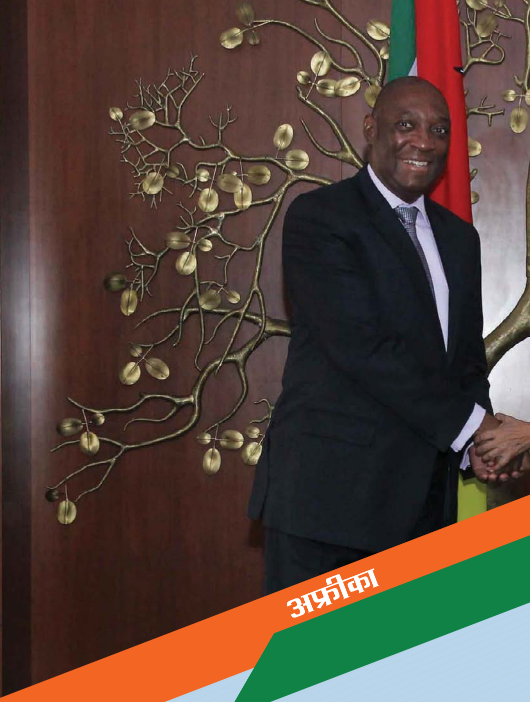

अफ्रीका

मोज़ाम्बीक

अर्थव्यवस्था

- विदेश मंत्री ओल्डेमिरो बलोई की यात्रा के दौरान, तेल और गैस के क्षेत्र में एक सहकारी संस्थागत ढांचे को स्थापित करने और द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए, भारत और मोज़ाम्बीक के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

डिप्लोमेसी

- विदेश मंत्री ओल्डेमिरो बलोई ने भारत का दौरा किया और विदेश मंत्री से विस्तार से चर्चा की।

अफ्रीका

युगांडा

डिप्लोमेसी

- युगांडा के विदेश मंत्री सैम कुटेसा ने 27–31 जुलाई 2014 तक भारत की यात्रा की और प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री से भेंट की।
- युगांडा के प्रतिनिधिमंडल में सूचना, संचार और प्रौद्योगिकी मंत्री, मत्स्य पालन राज्य मंत्री, निवेश राज्य मंत्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।

फोटो | वीडियो | स्नैपशॉट

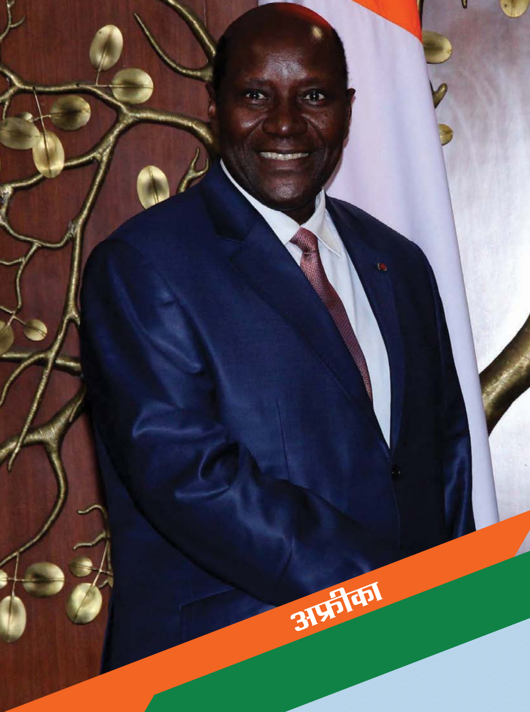

अफ्रीका

कोटे डी आइवरी

- आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री डेनियल कबलान डंकन ने नई दिल्ली में नवम्बर 2014 में विदेश मंत्री से मुलाकात की।

फोटो | वीडियो | स्नैपशॉट

VI BRICS SUMMIT
15 July 2014 Fortaleza
16 July 2014 Brasilia

MYANMAR 2014
9th EAST ASIA SUMM
Nay Pyi Taw, Myanmar 13 November 2014

विश्व मंच पर

बना रहा अपनी पहचान

शिखर सम्मेलन

डिप्लोमेसी

- ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री ने ब्राज़ील के शहर फोर्टालेज़ा की यात्रा की; जहाँ उन्होंने ब्रिक्स के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं।

ब्रिक्स

अर्थव्यवस्था

- ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित 50 बिलियन डॉलर की राशि वाले नए विकास बैंक का पहला अध्यक्ष एक भारतीय होगा।
- ब्रिक्स सदस्य देशों ने अल्पकालिक तरलता के लिए 100 बिलियन डॉलर की आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था स्थापित की।

फोटो   वीडियो   स्नैपशॉट

- भारत की पहल पर, संयुक्त राष्ट्र के सदस्य 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने के लिए एकमत से सहमत। संयुक्त राष्ट्र के 192 में से 177 सदस्यों की अभूतपूर्व संख्या ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।
- प्रधानमंत्री मोदी ने सितम्बर में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अपने संबोधन में इस दिवस को अपनाने के लिए प्रस्ताव पेश किया था।
- अंतर्राष्ट्रीय आंतकवाद का मुकाबला करने के लिए प्रधानमंत्री ने ठोस प्रयास करने का आह्वान किया और अंतर्राष्ट्रीय आंतकवाद पर एक विस्तृत नीति अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया।
- भारत ने संयुक्त राष्ट्र परिषद में सुधार की आवश्यकता को दोहराया।
- प्रधानमंत्री मोदी ने सभी को बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए एक व्यापक और संयुक्त प्रत्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई का आह्वान किया।

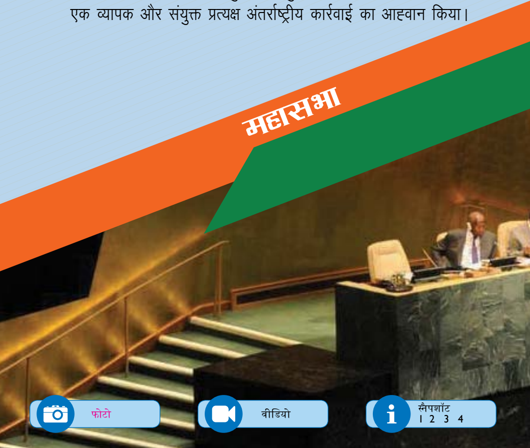

संयुक्त राष्ट्र

डिप्लोमेसी

- प्रधानमंत्री ने 12वें आसियान–भारत शिखर सम्मेलन में भाग लिया।
- विदेश मंत्री ने 12वें आसियान–भारत शिखर सम्मेलन में विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया।
- प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि भारत और आसियान देश 'महान भागीदार' हो सकते हैं और आसियान देशों को भारत के आर्थिक विकास के "नए युग" में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया।
- प्रधानमंत्री के "मेक इन इंडिया" अभियान की गूँज आसियान सदस्यों के बीच भी सुनाई दी।
- आसियान–भारत शिखर सम्मेलन के दौरान कई द्विपक्षीय बैठकें आयोजित की गईं।

शिखर सम्मेलन

आसियान–भारत

फोटो

वीडियो
1 2

स्नैपशॉट

शिखर सम्मेलन

डिप्लोमेसी

- प्रधानमंत्री मोदी ने 9वें ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लिया और आंतकवाद के सभी प्रारूपों के खिलाफ "वास्तविक अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी" का आह्वान किया।
- भारत ने इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया (आईएसआईएस) द्वारा फैलाई गई हिंसा और नफरत के खिलाफ की गई निंदा का समर्थन किया।
- भारत ने अन्य देशों से समुद्री

फोटो वीडियो स्नैपशॉट

ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन

विवादों पर अंतर्राष्ट्रीय कानून और नियमों का पालन करने का आह्वान किया।

अर्थव्यवस्था

- प्रधानमंत्री मोदी ने वस्तुओं और सेवाओं पर बराबर जोर देने के लिए एक "संतुलित" क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (आरसीईपी) का आह्वान किया।

शिखर सम्मेलन

जी–20

- विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के समूह जी–20 में प्रधानमंत्री मोदी ने कड़े शब्दों में काले धन को स्वदेश भेजने और करदाता विशिष्ट फैसलों में पारदर्शिता का मुदा उठाया।
- जी–20 में भारत की एक प्रमुख चिंता, रोजगार सृजन पर भी ध्यान केन्द्रित किया गया।
- जी–20 के लिए एक विकास–उन्मुख एजेंडा तैयार करने में भारत का एक प्रमुख योगदान था।
- भारत ने वस्तुओं के व्यापार की तरह सेवाओं को भी वैश्विक व्यापार तंत्र का एक हिस्सा बनाने के लिए तर्क दिया।
- प्रधानमंत्री ने अक्षय ऊर्जा के लिए एक वैश्विक केंद्र के निर्माण की मांग की।
- जी–20 नेताओं ने विज्ञप्ति जारी करके अमेरिका और भारत के बीच सफलता का स्वागत किया जिससे व्यापार सुविधा समझौते के पूर्ण और शीघ्र क्रियान्वन में सहायता मिलेगी और इसमें खाद्य सुरक्षा के प्रावधान शामिल हैं।

फोटो
वीडियो 1 2
स्नैपशॉट

शिखर सम्मेलन

भारत प्रशांत द्वीपसमूह सहयोग के लिए मंच

- भारतीय कूटनीतिक पहुँच के अंतर्गत प्रधानमंत्री ने फीजी में 12 प्रशांत द्वीपसमूह देशों के नेताओं के साथ बैठक की।
- प्रधानमंत्री ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 1 मिलियन डॉलर के विशेष अनुकूलन कोष की घोषणा की।
- प्रशांत द्वीप समूह के देशों – कुक द्वीपसमूह, किंगडम ऑफ टोंगा, तुवालु, नाउरु गणराज्य, किरिबाती गणराज्य, वानुअतु, सोलोमन द्वीप, समोआ, नियू, पलाऊ गणराज्य, संघीय राज्य माइक्रोनेशिया, मार्शल द्वीप, फिजी और पापुआ न्यू गिनी के लिए वीज़ा–ऑन–अराइवल सुविधा घोषित।
- प्रशांत द्वीपसमूह देशों के लिए सहायता अनुदान की राशि 1,25,000 डॉलर से बढ़ा कर 2,00,000 डॉलर की गई।

डिप्लोमेसी

- भारत ने काठमांडू में हुए सार्क शिखर सम्मेलन और इससे संबंधित बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लिया।
- पीएम मोदी ने सार्क क्षेत्र के लिए अपनी दृष्टिकोण के अनुसार पांच स्तंभ सूचीबद्ध किए
  - व्यापार
  - निवेश
  - सहायता
  - प्रत्येक क्षेत्र में सहयोग
  - निर्बाध कनेक्टिविटी के माध्यम से लोगों के बीच संपर्क

अर्थव्यवस्था और व्यापार

- बिजली के लिए ऊर्जा सहयोग हेतु फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
- भारत सार्क सदस्य देशों के साथ 'स्थाई' व्यापार संतुलन की दिशा में काम करेगा।
- 'व्यापार को सरल करने' के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 'सार्क बिजनेस ट्रेवलर कार्ड' का प्रस्ताव रखा।

शिक्षा

- दिल्ली में साऊथ एशियन यूनिवर्सिटी प्रत्येक सार्क देश की कम से कम एक यूनिवर्सिटी को भागीदार बनाएगी।
- भारत सभी दक्षिण एशियाई विद्यार्थियों से ऑनलाइन पाठ्यक्रमों और ई–पुस्तकालयों द्वारा जुड़ेगा।
- परिचालन शुरू होने पर भारत के राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क को पूरे सार्क क्षेत्र में विस्तारित किया जाएगा।

शिखर सम्मेलन

स्वास्थ्य

- भारत ने टीबी और एचआईवी के लिए सार्क क्षेत्रीय सुपरा रेफरेंस प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए फंड की कमी को पूरा करने की घोषणा की।
- भारत ने पोलियो–मुक्त देशों की निगरानी और चौकसी तथा वैक्सीन प्रदान करने के लिए समर्थन देने का प्रस्ताव रखा।
- चिकित्सा उपचार के लिए भारत आने वाले लोगों के लिए तत्काल चिकित्सा वीज़ा की घोषणा।

आधारभूत संरचना

- क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्र की आधारभूत परियोजनाओं को वित्त प्रदान करने हेतु भारत में विशेष उदेश्य इकाई स्थापित की जानी है।

अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी

- भारत ने 2016 में सार्क दिवस तक सार्क कृत्रिम उपग्रह को लांच करने की अपनी इच्छा जताई। यह उपग्रह सम्पूर्ण सार्क क्षेत्र को सेवाएं प्रदान करेगा।

सार्क

फोटो वीडियो स्नैपशॉट

शंघाई सहयोग संगठन

एक प्रभावशाली आवाज़

डिप्लोमेसी

- भारत ने एससीओ की पूर्ण सदस्यता के लिए औपचारिक आवेदन दिया।
- विदश राज्यमंत्री जनरल (डा०) वी० के० सिंह ने एससीओ में उपस्थिति दर्ज की। दिसंबर 2014 में असताना में सरकार के प्रमुखों की परिषद् की बैठक ।

- पहली बार विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज की देखरेख में भारत ने एससीओ ऊर्जा क्लब में भागीदारी की।

अर्थव्यवस्था

- भारतीय व्यापार जगत ने पहली बार एससीओ बिजनेस फोरम मीट में भाग लिया।

फोटो | वीडियो | स्नैपशॉट

मातृभूमि

की पुकार

प्रवासी

- न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वेयर गार्डन में भारत–अमेरिकी समुदाय ने भारी मात्रा में एकत्रित हो कर प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया।
- प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को 'मेक इन इंडिया' पहल में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया और MyGov वेबसाईट की सहायता से उनसे बातचीत की।
- 'स्वच्छ गंगा' पहल' में भागीदारी के लिए प्रवासी भारतीयों को आमंत्रित किया गया।

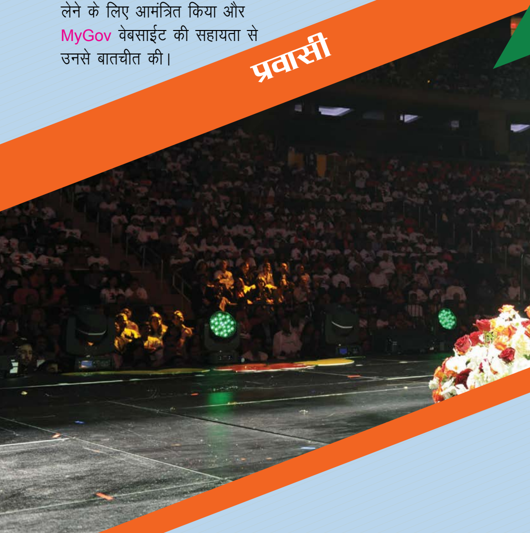

मेडिसन स्क्वेयर गार्डन, न्यूयॉर्क

- पीएम मोदी ने 2022 तक 'सभी के लिए आवास' के बारे में अपने विचार साझा किए।
- पीआईओ के लिए आजीवन वीज़ा और पीआईओ तथा ओसीआई कार्ड को मिला कर एक करने की घोषणा।
- प्रधानमंत्री ने अमेरिकी नागरिकों के लिए लम्बी–अवधि के पर्यटक वीज़ा और अमेरिकी नागरिकों के लिए वीज़ा–ऑन–अराइवल सुविधा की भी घोषणा की।

फोटो वीडियो स्नैपशॉट

- प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के सदस्यों की भारी भीड़ को संबोधित किया और 15 जनवरी तक पीआईओ और ओसीआई कार्ड को मिला कर एक करने की घोषणा की।

प्रवासी

आल्फोन्स एरिना, सिडनी

फोटो

वीडियो

स्नैपशॉट

- विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने लंदन के पहले क्षेत्रीय प्रवासी भारतीय दिवस का उदघाटन किया और सभी प्रतिभागियों से 2015 में गाँधीनगर में होने वाले प्रवासी भारतीय दिवस में भाग लेने के लिए कहा।

यूके में क्षेत्रीय प्रवासी भारतीय दिवस

फोटो

वीडियो
1 2

स्नैपशॉट

- विदेश मंत्री ने नवम्बर 2014 में पोर्ट लुईस, मॉरिशस में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया जो भारतीय अनुबंधित श्रमिकों (गिरमिटिया) के मॉरिशस में प्रथम आगमन के 180 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 2 नवम्बर को मॉरिशस के अप्रवासी घाट पर आयोजित किया गया था।

प्रवासी

मॉरिशस में अप्रवासी दिवस की 180वीं वर्षगाँठ का स्मरणोत्सव

फोटो

वीडियो

स्नैपशॉट
1 2

नागरिक–केन्द्रित सेवाएं

पासपोर्ट

- पासपोर्ट पुस्तिकाओं की कमी को दूर करने के लिए कदम उठाए गए हैं। एक करोड़ पासपोर्ट का आरक्षित भंडार स्थापित किया गया है।
- उत्तर–पूर्वी राज्यों में पासपोर्ट सेवा केन्द्रों के खोलने के काम में तेजी लाई गई।
- देश भर में कई स्थानों पर पासपोर्ट मेले और पासपोर्ट कैम्प आयोजित किए गए हैं। 2015 के दौरान इस प्रकार के पासपोर्ट मेलों और पासपोर्ट कैम्पों का

फोटो | वीडियो | स्नैपशॉट

आम आदमी की सेवा में

विस्तार देश के सभी जिलों तक किया जाएगा।

- पासपोर्ट जमा करने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया और अब स्वयं सत्यापित किए गए दस्तावेज़ स्वीकार्य हैं।

स्वच्छ भारत अभियान

- विदेश सचिव सुजाता सिंह के नेतृत्व में विदेश मंत्रालय ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की।

तकनीक

- भारत द्वारा हस्ताक्षरित संधियों का डेटाबेस ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया है।
- वास्तविक समय में सूचना को प्रसारित करने और जनता की समस्याओं पर ध्यान देने के लिए फेसबुक और अ सहित सोशल मीडिया का उपयोग किया जा रहा है।
- मोबाइल प्रौद्योगिकी के प्रयोग में वृद्धि, हज के दौरान मक्का और मदीना में रहने वाले हज यात्रियों के आवास का पता लगाने के लिए पहली बार जीपीएस मोबाइल एप्लीकेशन का प्रयोग किया गया।

उपसंहार

अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 26 जनवरी, 2015 को भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बनने के निमंत्रण को स्वीकृति दे दी है। ऐसा पहली बार होगा जब विश्व के प्राचीनतम लोकतंत्र का नेता, विश्व के विशालतम लोकतंत्र के गणतंत्र दिवस समारोह में भागीदारी करेगा।

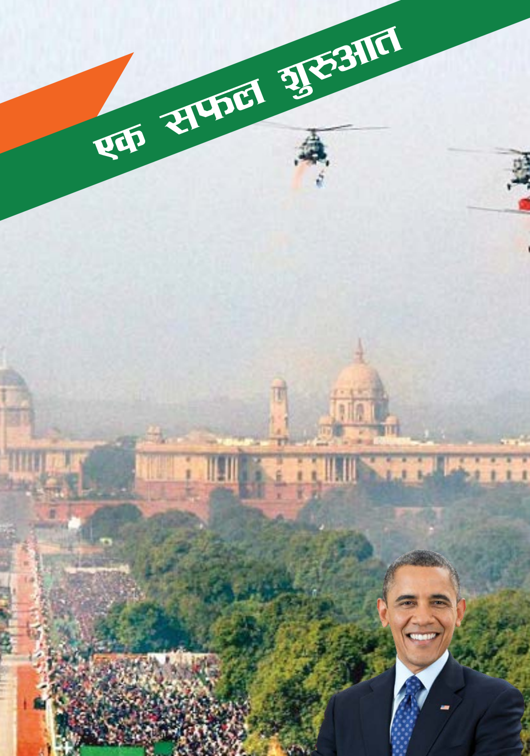
एक सफल शुरुआत

विदेश मंत्रालय की एक सार्वजनिक राजनय पहल